ject to augmentation in availability of LPG.

Gas Based Power Plant in Kerala

489. SHRI THOMAS KUTHIRAVATTOM:
SHRI P.K. KUNJACHEN:

Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether Government are considering a proposal to set up gas based power plants to generate electricity;

(b) whether a request for starting such a power plant in Cochin has been received from Kerala Government; and

(c) whether Government will consider this request and what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI KALPNATH RAI): (a) to (c) Gas-based power plants are being set up by organisations like the National Thermal Power Corporation and some State Electricity Boards.

A Feasibility Report in regard to setting up a 90 MW Combined Cycle Power Plant, based on LSHS/fuel oil/natural gas, at Brahmapuram, Cochin was received by the Central Electricity Authority from the Kerala State Electricity Board in April, 1988. The proposal could be processed for techno-economic approval after the fuel availability is confirmed, the requisite inputs have been tied up and the necessary clearances have been obtained by the State Electricity Board.

सही उपभोक्ताओं को घरेलू गैस के दूसरे सिलेण्डर का जारी किया जाना

490 **श्री सुनील कुमार पट्टनायक** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र मे इंडियन आयल कारपोरेशन के क्षेत्रीय अधिकारी/निरीक्षक/बिक्री अधिकारी से यदि उपभोक्ता अपने मूल गैस कनेक्शन के आधार पर दूसरा सिलेन्डर प्रदान करने के लिए अनुरोध करता है तो उन्हें इन अधिकारियों द्वारा अनुमति नहीं दी जाती, जबकि उपरोक्त कारपोरेशन के इसी दर्जे के अधिकारियों द्वारा इस बारे में तुरन्त अनुमति दे दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार क्षेत्रीय प्रबन्धकों/निरीक्षकों/बिक्री अधिकारियों को इस प्रकार की हिदायतें देने का का विचार रखती है कि वे दूसरे सिलेन्डर की अनुमति दे दिया करें; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बहम दत्त): (क) से (घ) इंडियन आयल कारपोरेशन की नीति के अनुसार कुछ पदधारी अधिकारियों को डी बी सी **जारी करने** के लिए प्राधिकृत किया गया है। इनमें क्षेत्र अधिकारी शामिल नही है। वितरकों को इस बात के अनुदेश हैं कि देश मे जब उपभोक्ता चाहे उसे डी बी सी जारी कर दिया जाये। फिर भी, जब कभी एल पी जी की सप्लाई मे बैकलॉग या उत्पाद की समस्याएं आदि होती हैं तो स्थिति के सामान्य होने तक डी बी सी जारी करना अस्थायी रूप मे रोक दिया जाता है।

Telephone Exchange in Marangattupilly, Kerala

491. SHRI THOMAS KUTHIRAVATTOM: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the number of telephone connections which have been provided in Marangattupilly telephone exchange in Kottayam district of Kerala and what is the total number of applicants on waiting list at present;

(b) whether Government propose to expand this telephone exchange, if so, what are the details thereof; and

(c) whether the Department owns land and building in this area?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) Marangattupilly is served by a 90 Lines MAX III Exchange. The number of work-